श्री सभापति: आप विषय पर आइए।

श्री मोहम्मद अली खान: मैं आपसे मुतालबा करूंगा आपकी तवस्सुत से मरकज़ी सरकार से कि इसको भी खत्म करके तमाम मुसाफिर जो सफर करते हैं, उनको मसावियाना हुकूक के साथ बस में सफर करने की इजाजत दी जाए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

† **جناب محمد علی خان:** میں آپ سے مطالبہ کرونگا آپ کے توسط سے مرکزی سرکار سے کہ اس کو بھی ختم کرکے تمام مسافر جو سفر کرتے ہیں، ان کو مساویانہ حقوق کے ساتھ بس میں سفر کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، دھنیواد۔

श्री सभापति: आपका भी शुक्रिया कि आपने समय के अंदर समाप्त किया।

Problems being faced by Gold/Silver traders and workers due to misuse of IPC Section 411

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को सारे हिन्दुस्तान में सोने-चांदी का व्यवसाय करने वाले कारीगरों की पीड़ा से अवगत करना चाहता हूं। सारे हिन्दुस्तान में भारतीय दंड विधान की धारा 411 की आड़ में लाभ प्राप्त करने की नीयत से इस धारा के क्रियान्वयन के दुष्परिणाम स्वरूप पूरे स्वर्णकार समाज के कारीगर पीड़ित हैं। उनके खिलाफ असत्य मुकदमे कायम किए जाते हैं जिसके कारण कई आत्महत्या के मामले भी सामने आए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को भारतीय दंड विधान की धारा 411 के संबंध में बताना चाहता हूं कि जब औने-पौने दामों में कोई चीज़ खरीदी जाए और उसका कोई रिकॉर्ड न रखा जाए, तब यह धारा गठित होती है। लेकिन रिकॉर्ड रखने के बाद, बाजार भाव पर सामान खरीदने के बाद वास्तविक चोरी तो चोर की नहीं होती है, बल्कि सुनार की होती है, कारीगर की होती है। वह एक बार तो दाम विक्रेता को देता है और फिर उसको पुलिस से पीड़ित होना पड़ता है। महोदय, तीसरे उसका सामान जब्त होता है। इस प्रकार से तीन-तीन चोरियां, सर्राफों और स्वर्णकारों की होती हैं। भगवान ने जिन्हें अपने आपको सजाने और आदमियों को सजाने का कर्तव्य निर्धारित किया है, उनकी बहुत दुर्दशा है। उनके खिलाफ पुलिस की इस प्रकार की कार्रवाई से वे पीड़ित होकर बहुत दुखी और परेशान हैं। अत: मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय दंड विधान की 411 में एक 'परन्तुक' जोड़ दिया जाए कि यदि बाजार दाम से सामान खरीदा है और सोना-चान्दी का व्यवसाय करने वालों ने record रखा है, तो उनके विरुद्ध पुलिस की इस प्रकार की उत्पीड़न करने वाली कार्रवाई न की जाए। किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि कोई चोर है। हमने आधार कार्ड की कॉपी पर दस्तखत कराए हैं और रिकॉर्ड रखा है। उसके बावजूद उसके खिलाफ धारा 411

†Transliteration in Urdu script.

[श्री कैलाश सोनी]

का प्रयोग किया जाता है। मैं आपके माध्यम से पुन: विधि मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारतीय दंड विधान की धारा 411 में एक परन्तुक जोड़ा जाए, ताकि स्वर्णकारों का उत्पीड़न रुक सके।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

Problems of tea plantation workers and tea garden owners

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, Darjeeling tea is the first thing we have in the morning which gives us our first smile of the day. It is high time that the Government pays back the workers and tea garden owners the much deserving return gift. Sprawling tea gardens in the green foothills of West Bengal's Dooars region provides livelihood to majority of the area's tribal population. Unfortunately, the market rate of tea and the overall cost of producing it has forced many tea gardens to close down, which, consequently, forced the labourers to look for other sources of earning. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SHANTA CHHETRI: Seeing the plight of tea workers, the State Government started providing rice and atta at Rs. 2 per kg. *, who calls himself a former * had promised to look into the issues of the plantation workers. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. You don't bring the name of Prime Minister and Chief Ministers. ...*(Interruptions)*... Even if it is a fact, that is not relevant to this. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SHANTA CHHETRI: Up till 2011, wages of tea workers were only Rs. 67 per day. Ever since, our Chief Minister, Mamata Banerjee, has gradually increased it to its present rate of Rs. 176 per day and formed the Tea Directorate for welfare of tea workers.

MR. CHAIRMAN: What is your demand or suggestion?

SHRIMATI SHANTA CHHETRI: Therefore, I urge upon the hon. Minister of Commerce and Industry to implement the Minimum Wages Act in tea gardens, provide subsidy to the tea gardens for modernisation and re-plantation, urgently set up centrally-located hospitals for tea workers and dependents, provide scholarships for children of

*Not recorded